रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1690] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 5, 1936
No. 1690] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 5, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

का. आ. 2168 (अ).----पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के अधीन भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 310 (अ) तारीख 4 फरवरी, 2014, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 4 फरवरी, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्तः विचार किया गया है ;

और क्योंगलासा अल्पाइन अभ्यारण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यारण कहा गया है) पूर्वी जिला, सिक्किम के नाथूला सिरे की ओर जवाहरलाल नेहरु राष्ट्र के साथ-साथ स्थित है । अभ्यारण का क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है और अभ्यारण अधिक ऊंचाई के प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण वन्य प्राणी पर्यावास क्षेत्र का गठन करता है और इसकी ऊंचाई की प्रवणता 3200 मीटर से 4200 मीटर की रेंज में है । स्थलाकृति भू-दृश्य के व्यापक रेंज में कुछ दुर्लभ संकटापन्न भू-आर्किडों और राष्ट्रोडेंड्रोंस जो लंबे जूनीपरों के बीच फैले हुए हैं, को प्राश्रय मिलता है ;

और विद्यमान महत्वपूर्ण पादपों में से सिल्वर फर एक है। राडोडेंड्रान नेवियम जो कि सिक्किम का राज्य वृक्ष है तथा टाइबैटकम जो भू-स्लीपर आर्किड है लुप्त होने के कगार पर है को यहां बोया गया है और अब इनकी यहां काफी संख्या है ;

और अभ्यारण में भू-प्राणियों में प्राइमूलाज, जंगली स्ट्राबेरीज, आइरिसस, पोप्रीज और दुर्लभ रूप से दृश्यमान पैनाक्स सूडो-जिनसेंग की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं । पाइक्रोरहिजा सकरोकुलारीफ्लोरा (कुटकी) नार्डोस्टेकिस ग्रेंडीफ्लोरा (जटामासी), एकोनीटम फैरोक्स (नाइलो बिख) तथा पोडोफाइलम इमोडी जैसे चिकित्सीय पादप हैं ;

और अभ्यारण की निचली ऊंचाइयों पर मृदा को बांधकर रखने वाली बांस की अरुंदीनेरिया प्रजातियां हैं । यह क्षेत्र प्रायः जब प्राइमूलाज बर्फ से बाहर झांकता है और राडोडेंड्रोंस की कोपलें निकलती हैं, मई तक बर्फ से आच्छादित रहता है । जून-जुलाई तक यहां पूरी तरह से फूल खिलते हैं । बहुत सी प्रजातियों की फूल खिलने की ऋतु जब पोलीगोनम प्रजातियों के अंतिम फूल सूख जाते हैं, अक्तुबर तक जारी रहती है;

और प्राणियों की विविधता में गोरालय, सेरो लाल पांडा, हिमालयन काला भालू, कस्तूरी मृग, तेंदुआ, तिब्बती लोमड़ी पीले गले वाले मार्टेन, वीजल और हिमालयन मर्मोड शामिल हैं । महत्वपूर्ण आवी-प्राणी विविधता लाल तीतर, मोनल तीतर, स्टायर ट्रेगोपन, स्नोपार्टिजस, लाफिंग थ्रूसस, गुलाब के फिंचस, रेड बिल्ड चोक्स, फोर्टेल्स, रेडस्टार्क, काले पंखों वाली चील, केस्ट्रेल, लावरगेयर और ग्रिफोन गिद्ध, अग्निपुंछ सनबर्ड तथा प्रवासी पक्षियों की विभिन्न जातियां यहां व्यापक रूप से प्रदर्शित होती हैं ।

और इस अभ्यारण की प्रमुख विशिष्टता अनुसूचित जानवरों की संख्या जिसे यह प्राश्रय देता है [वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)] । जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम संरक्षण दिया जाता है के साथ इसमें मुख्य आवासी लाल पांडा और गृहकुक्कुट पक्षी तथा तीतर हैं ;

और, यह आवश्यक है कि क्योंगलूसा अल्पाइन अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसमें वन्य जीवन तथा उसके पर्यावरण को संरक्षित और प्रसारित करने के दृष्टिकोण से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए ;

और, क्योंगलूसा अल्पाइन अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करना और उद्योगों, प्रक्रियाओं, उद्योगों के वर्ग, प्रचालन या प्रक्रियाओं को निषिद्ध करना आवश्यक हो गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिक्किम राज्य क्योंगलूसा अल्पाइन अभ्यारण्य की सीमा से दो सौ मीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार क्योंगलोसा अल्पाइन अभ्यारण से 25 मीटर से 200 मीटर के बीच परिवर्तित होता है । पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 25 मीटर होगा जहां ढाल 45 डिग्री से अधिक है और जो पारिस्थितिकी रूप से दुर्बल अभ्यारण के पूर्वी हिस्से में है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 200 मीटर होगा । उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार राती छूह नदी के बाहरी किनारे तक होगा जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का निर्माण करती है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर 27^0 24' 5" उत्तरी अक्षांश और 88^0 41' 54" पूर्व देशांतर पूर्वी ओर है (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 1) 27^0 23' 41" उत्तरी अक्षांश और 88^0 42' 48" पूर्व देशांतर पश्चिमी ओर है (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 3); 27^0 25' 13" उत्तरी अक्षांश और 88^0 43' 49" (मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 2) 27^0 22' 36" उत्तरी अक्षांश और 88^0 43' 50"(मानचित्र का निर्देश बिन्दू संख्या 5)

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिसूचना के **उपाबंध 1** के रूप में संलग्न है ।

(4) क्योंगलोसा अल्पाइन अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 2 ग्रामों की सूची उसके अक्षांश और रेखांश के साथ इस अधिनियम के **उपाबंध 2** के रूप में संलग्न है :

परंतु उपाबंध 2 राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान में पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(5) उपाबंध 2 में दिए गए ग्रामों की सूची का राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय उसको अतिरिक्त पुनः निरीक्षण और पुष्टि की जाएगी ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर योजना** --(1) राज्य सरकार स्थानीय लोगों और निम्नलिखित संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में

प्रकाशन की तारीख से द□ वर्ष के भीतर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार के विचार और अनुमाद्दन के लिए एक जाम्मल मास्टर याज्ञना तैयार करेगी, अर्थात्:-

(i) वन, पर्यावरण और वन्य जीव प्रबंधन;

(ii) सिक्किम पुलिस;

(iii) शहरी आवास विकास;

(iv) पर्यटन:

(v) ग्रामीण प्रबंधन और विकास;

(vi) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(vii) लाफ़ निर्माण विकास;

(viii) भू-राजस्व; और

(ix) आपदा प्रबंधन ।

(2) जाम्मल मास्टर याज्ञना निम्नीकृत क्षेत्रों के पुनरुद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, कैचमेंट क्षेत्रों के प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, भू जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य परिप्रेक्ष्यों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है के लिए उपबंध करेगी ।

(3) जाम्मल मास्टर याज्ञना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, वनों की किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्रों और बागवानी क्षेत्रों, झीलों, अन्य जल निकायों और उद्यमी इकाइयों क□ चिन्हित करेगी ।

(4) जाम्मल मास्टर याज्ञना में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पैरा 4 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के विनियमन के लिए उपाय अंतर्विष्ट होंगे ।

(5) जाम्मल मास्टर याज्ञना विधिक रूप से अभिलिखित गैर वन भूमि क□ छूट प्रदान करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय,-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों क□ प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भूमि उपयाग-** वन भूमि, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और मनारंजन के प्रयाजनों के लिए चिन्हित खुले क्षेत्रों के भूमि उपयाग क□ वाणिज्यिक या औद्याोगिक संबंधी विकास गतिविधियों में परिवर्तित करने क□ पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्रों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु कृषि भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जाम्म के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जाम्म मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमाद्दन से, विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों क□ पूरा करने के लिए, और संख्या 12, 25, 26, 30 और 31 में सूचीबद्ध कार्यकलाप के लिए, और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(i) वर्षा जल संचयन;

(ii) ग्रामीण उद्याग जिसके अंत ग्रामीण दस्तकार हैं आदि

(iii) लघु उद्याग ज□ प्रदूषण नहीं कर रहे हैं ;

(iv) पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाएं जैसे गृहों में आवास, रोप, वे, कियोस्क, फनीकुलर, आदि और

(v) सुरक्षा बल शिविर :

परंतु यह और कि जनजातीय उपयाग से भूमि के उपयाग में गैर जनजातीय उपयाग के लिए काई परिवर्तन राज्य सरकार के पूर्व अनुमाद्दन के बिना और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों का अनुपालन किए बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु ये भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भूमि अभिलेखों में उद्भूत होने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति के विचारों को अभिप्राप्त करने के पश्चात् एक बार ठीक किया जाएगा और उक्त त्रुटि के ठीक करने से केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संसूचित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि त्रुटि के उक्त ठीक करने में किसी भी दशा में सिवाय इस पैरा में उपबंधित के भूमि उपयोग का कोई परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(2) **प्राकृतिक जलस्रोत--**सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन--**पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के संनिर्माण की सिवाय पैरा 3 की सारणी के स्तम्भ (2) के अधीन गृहों में ठहरने, रोपवे, क्याोस्क, फन्कुलर्स आदि जैसी पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के, मंजूरी नहीं होगी ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(4) **नैसर्गिक विरासत**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संभारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(6) **वायु प्रदूषण** - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग सिक्किम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(7) **बहिस्रावों का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) ठोस अपशिष्ट - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(9) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

4. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलाप** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी कार्यकलापों का प्रशासन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार होगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां**	हां	-	-	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए, सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयों का प्रतिषेध है । (ख) खनन संक्रियाए सर्वथा, 1995 की रिट याचिका (सी) सं0 202 में टी.एन.गोडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4.8.2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21.4.2014 के आदेशों के अनुसार होंगी ।
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्रदूषणकारी नए उद्योग या विद्यमान उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
5.	किन्हीं परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	
6.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में तत्काल प्रभाव से कोई नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
7.	जलाने की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	हां	-	-	

IndiaCode

8.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
9.	नई बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (101 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
10.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों को खड़ा करना ।	-	हां	-	अंडरग्राउंड केबिलिंग का संवर्धन करना ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मत्स्य पालन	-	-	हां	
12.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाए ।
13.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना	-	हां	-	
14.	वनस्पतिक बाड़ लगाना			हां	
15.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
16	विद्यमान सड़कों का चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।

IndiaCode

17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।
18.	विदेशी प्रजातियों का लाना	-	हां	-	
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे अभ्यारणय के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि ।	-	हां	-	
20.	पहाड़ी ढालानों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अननुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकार करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
25.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	-
26.	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं ।
27.	नए काष्ठ आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी ।
28.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का	-	हां	-	

IndiaCode

	संग्रहण				
29.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जा‍म में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के जिसके अंतर्गत मद संख्या 12, 25, 30 और मद संख्या 31 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों क□ विनियमित किया जाएगा और उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
30.	घर में रहना, रा‍प्र वे, क्या‍स्क, फनिकुलर आदि जैसी पारिस्थितिकी - पर्यटन सुविधाएं	-	हां	-	
31.	सुरक्षा बल शिविर	-	हां	-	
32.	प्लास्टिक के थैलों का उपया‍ग	हां	-	-	

5. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा‍म मानीटरी समिति—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जा‍म के प्रभावी मानीटरी के लिए सिक्किम राज्य के लिए एक समिति गठित की गयी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा‍म मानीटरी समिति (एसईएसजेडएमसी), ज□ निम्नलिखित से मिलकर बनी, अर्थात् :—

(i) मुख्य सचिव, — अध्यक्ष ;

(ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन सिक्किम सरकार — सदस्य ;

(iii) **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्रालय का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(iv) पीसीसीएफ – सिक्किम सरकार — सदस्य ;

(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बा‍र्ड का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(vi) सिक्किम सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि **(एक वर्ष की अवधि के लिए)** — सदस्य ;

(vii) ग्रामीण प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(viii) गा□विंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, सिक्किम का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(ix) कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(x) शहरी विकास और आवास विकास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधि — सदस्य ;

(xi) संबद्ध जिला कलक्टर — सदस्य ;

(xii) प्रभागीय वन अधिकारी (पी ए प्रभारी) — सदस्य ;

(xiii) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) — सदस्य सचिव ।

(2) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा‍म समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन क□ मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जा‍म में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा‍म मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय क□ निर्दिष्ट की जाएगी ।

IndiaCode

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जा॒न में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा॒न मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों क॒ निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा॒न मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, ज॒ इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम ह॒गा।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा॒न मानीटरी समिति विषय-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्य॒गिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों क॒ अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा॒न मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उस वर्ष की 30 जून तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क॒ **उपाबंध 3** में दिए गए प्रा॒फार्मा में, की गई कार्रवाई की अपनी वार्षिक रिप॒र्ट प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जा॒न मानीटरी समिति क॒ अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश ज॒ वह उपयुक्त समझे दे सकेगा ।

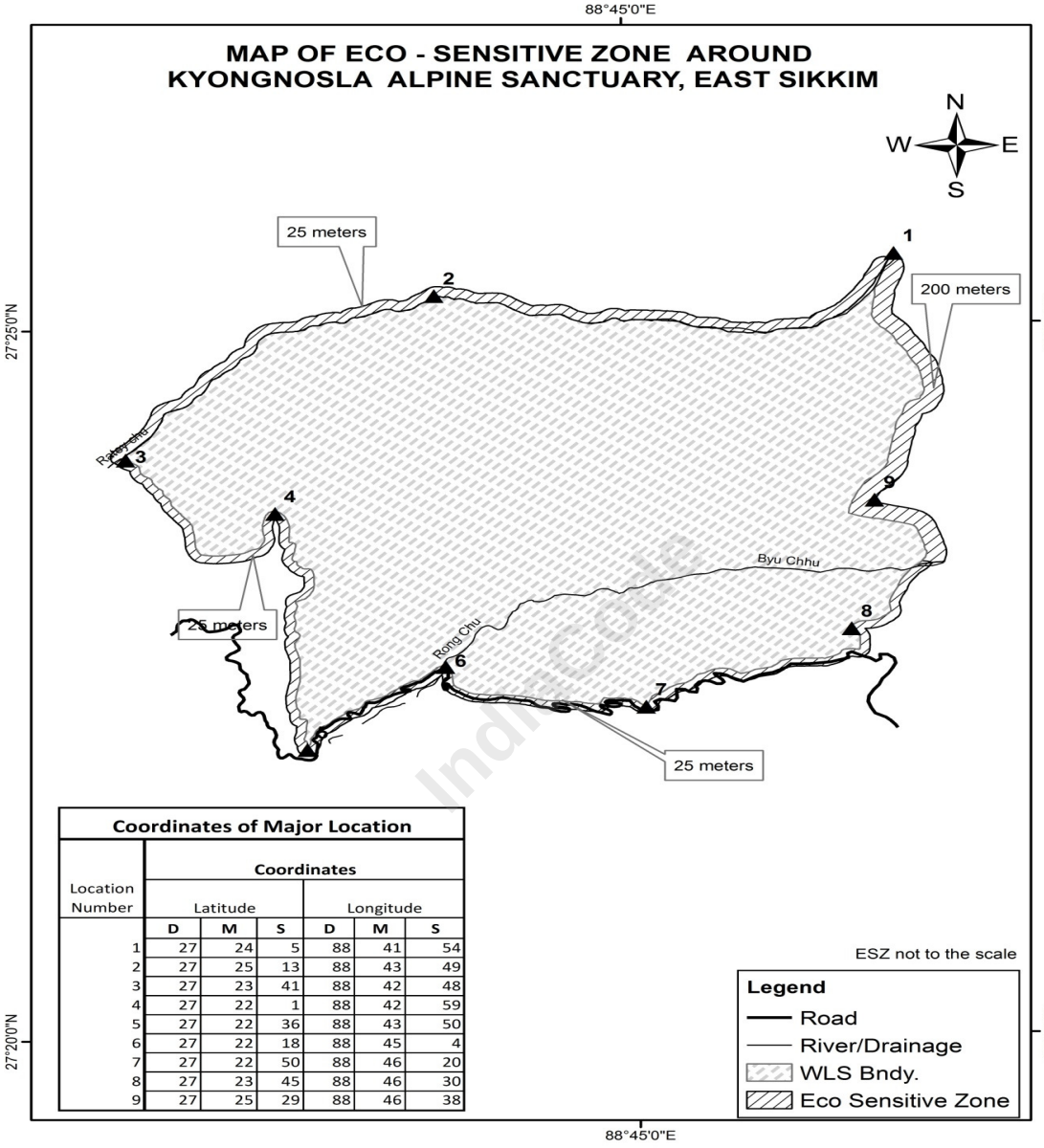
[फा. सं. 25/14/2013-ईएसजेड-आर ई]

डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध-1

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का बाहरी अक्षांश और रेखांश तथा उनके विस्तार को दर्शित करने वाला मानचित्र



Coordinates of Major Location

Location Number	Coordinates					
	Latitude			Longitude		
	D	M	S	D	M	S
1	27	24	5	88	41	54
2	27	25	13	88	43	49
3	27	23	41	88	42	48
4	27	22	1	88	42	59
5	27	22	36	88	43	50
6	27	22	18	88	45	4
7	27	22	50	88	46	20
8	27	23	45	88	46	30
9	27	25	29	88	46	38

उपाबंध-2

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन क्योंगसोला अल्पाइन अभ्यारण्य पूर्वी सिक्किम के भीतर आने वाले ग्राम

क्र.सं.	गांव का नाम	रेखांश			अक्षांश		
		डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1.	कारपोंग	27	22	12	88	41	34
2.	चांगू	27	22	14	88	44	40

उपाबंध-3

कार्रवाई की गई रिपार्ट का प्राफ़ार्मा - राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जाम मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और डाटा
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त क एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जाम्रल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान (पारिस्थितिक संवेदी जाम्रवार)
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जाम्रवार)
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जाम्रवार)
   के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश, ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जाम्रवार)
   के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जाम्रवार)
8. महत्ता का काई अन्य विषय ।

[फा. सं. 25/14/2013-ईएसजेड/आरई]

डा. जी.वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

S.O. 2168(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 310(E), dated the 4th February, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 4th February, 2014;

And whereas, suggestions received in respect of the proposed draft notification have been considered by the Central Government;

And whereas, the Kyongnosla Alpine Sanctuary (hereinafter referred to as the Sanctuary), lies along the JawaharLal Nehru Road on the way to Nathula corner of the East district, Sikkim covering an area of 31 square kilometers and constitutes a critical wildlife habitat area for the high altitude fauna with an altitudinal gradient ranging from 3200 meters to 4200 meters and wide range of topographical landscape which harbours some rare, endangered ground orchids and rhododendrons interspersed among tall junipers;

And whereas, the silver fir is among the important plants present and *Rhododendron nevium,* the state tree of Sikkim and *Cypripedium tibeticum* the ground slipper orchid that are on the verge of extinction, have been introduced here and now has sizable population;

IndiaCode

And whereas, in the sanctuary the ground flora includes different species of primulas, wild strawberries, irises, poppies and the rarely seen *Panax pseudo- ginseng and* medicinal plants such as *Picrorhiza scrophulariflora (*Kutki), *Nardostachys grandiflora (*jatamasi), *Aconitum ferox*(Nilo Bikh) and *Podophylum emodi;*

And whereas, the lower elevation of the sanctuary is occupied with soil binding bamboo *Arundinaria species* and is snow covered often up to May when primulas pop up through the snow and rhododendrons come into bud and comes into full bloom by June–July. Flowering season for many species continue right through to October when *Polygonum* species the last to flower dries up;

And whereas, the faunal diversity includes goral, serow, red panda, himalayan black bear, musk deer, leopard, tibetan fox, yellow-throated martens, weasel and himalayan marmot and important avi-faunal diversity exhibits wide array of endangered and endemic populations such as blood pheasant, monal pheasant, satyr tragopan, snow partridges, laughing thrushes, rose finches, red- billed choughs, forttails, redstart, black- winged kite, kestrel, lammergeyer and griffon vulture, fire- tailed sunbirds and various species of migratory birds;

And whereas, the major significance of this sanctuary is the number of scheduled animals[Specified in Schedule I of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972)] in the form of red panda and different species of gallinaceous birds and pheasants;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Kyongnosla Alpine Sanctuary and to protect and propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment;

And whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Kyongnosla Alpine Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-Sensitive Zone.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 200 metres from the boundary of the Kyongnosla Alpine Sanctuary in the State of Sikkim as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 25 meters to 200 meters from the boundary of the Kyongnosla Alpine Sanctuary. The extent of Eco-sensitive Zone shall be 25 meters where the slope is more than 45 degree and in the eco-fragile eastern part of the sanctuary, the extent of Eco-sensitive Zone shall be 200 meters. In the northern and north-western part, the extent of eco-sensitive zone shall be up to the outer bank of the river Ratey Chhu, which forms the boundary of the eco-sensitive zone.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 27º 24’ 5" N latitude and 88º41’54”E longitude towards east (Reference point No.1 of map); 27º23’41"N latitude and 88º42’48"E longitude towards west (Reference point No. 3 of map); 27º25’13"N latitude and 88º43’49"E longitude towards north(Reference point No. 2 of map) and 27º22’36"N latitude and 88º43’50"E longitude towards south (Reference point No. 5 of map).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list of two villages falling within the Kyongnosla Alpine Sanctuary Eco-sensitive Zone alongwith their longitudes and latitudes at prominent points is appended to this notification as **Annexure II:**

Provided that the Annexure II shall be subject to the confirmation by the State Government in the Zonal Master Plan.

(5) The villages as given in Annexure II shall be further revisited and confirmed by the State Government while preparing the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—**(1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the consideration and approval of the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, in consultation with the local people and with the following concerned State Departments, namely:-

(i) Forest, Environment and Wildlife Management;
(ii) Sikkim Police;
(iii) Urban Housing Development;
(iv) Tourism;
(v) Rural Management and Development;
(vi) Irrigation and Flood Control;
(vii) Public Works Development;
(viii) Land Revenue; and
(ix) Disaster Management.

(2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of ecology and environment that need attention.

(3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, lakes, other water bodies and entrepreneurial units.

(4) The Zonal Master Plan shall contain the measures as may be specified by the Central Government or the State Government, for regulation of activities specified under column (2) of the table specified in paragraph 4.

(5) The Zonal Master Plan so prepared shall be co-terminus with the regional development plan.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land Use.-**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zonemay be permitted on the recommendation of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC), and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents, and for the activities listed at item numbers 12, 25, 26, 30 and 31 specified under column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Rainwater harvesting,
(ii) Cottage industries including village artisans, etc.,
(iii) Small scale industries not causing pollution,
(iv) Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc; and
(v) Security Forces Camp:

Provided further that no use of triballand shall be permitted for commercial or industrial related development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of SESZMC, only once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(2) **Natural Springs.—**The catchment areas of all springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and strict guidelines be drawn up for the prohibition of development activities at or near these areas.

(3) **Tourism.—**The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone which shall form part of the Zonal Master Plan shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity specified at item No. 30 relating to eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc. under column (2) of the Table in paragraph 4;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and recommendation of the SESZMC.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and be preserved and proper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plans shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.—**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

IndiaCode

(6) **Air pollution.—**The Environment Department or the State Forest Department of Sikkim shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(7) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(8) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(9) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998.

(10) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, SESZMC shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations in force.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Indiacode

TABLE

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad *Vs.* UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation *Vs.* UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Felling of trees.	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
3.	Setting up of saw mills.	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

5.	Use or production of any hazardous substances.	Yes	-	-	
6.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Yes	-	-	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Yes	-	-	
8.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
9.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the microhydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW), which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
10.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	-	-	Yes	
12.	Rain water harvesting.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
13.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
14.	Vegetative fencing			Yes	
15.	Organic farming.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species.	-	Yes	-	
19.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Yes	-	-	
20.	Protection of hill slopes and river banks.	-	Yes	-	
21.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	

IndiaCode

22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	-	Yes	-	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of green technology for all activities.	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
26.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.
27.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
28.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
29.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed at item numbers 12, 25, 30 and 31. In the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be regulated and kept at the minimum.
30.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
31.	Security Forces Camp		Yes		
32.	Use of plastic carry bags.	Yes	-	-	

IndiaCode

5. **State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-** (1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) for the State of Sikkim comprising of:-

(i) Chief Secretary, Government of Sikkim- Chairman

(ii) Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim- Member;

(iii) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change –Member;

(iv) PCCF, Government of Sikkim- Member;

(v) Representative of State Pollution Control Board-Member;

(vi) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment to be nominated by the Government of Sikkim (for a term of one year) – Member;

(vii) Representative of Rural Management Department, Government of Sikkim – Member;

(viii) Representative of Govind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development, Sikkim– Member;

(ix) Representative of Agriculture Department, Government of Sikkim – Member;

(x) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim – Member;

(xi) Concerned District Collector-Member;

(xii) Divisional Forest Officer (In-charge of PA) – Member;

(xiii) Chief Conservator of Forest (Wild Life) – Member Secretary.

(2) The SESZMC shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the SESZMC or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities as of 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests as per proforma given in **Annexure III**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

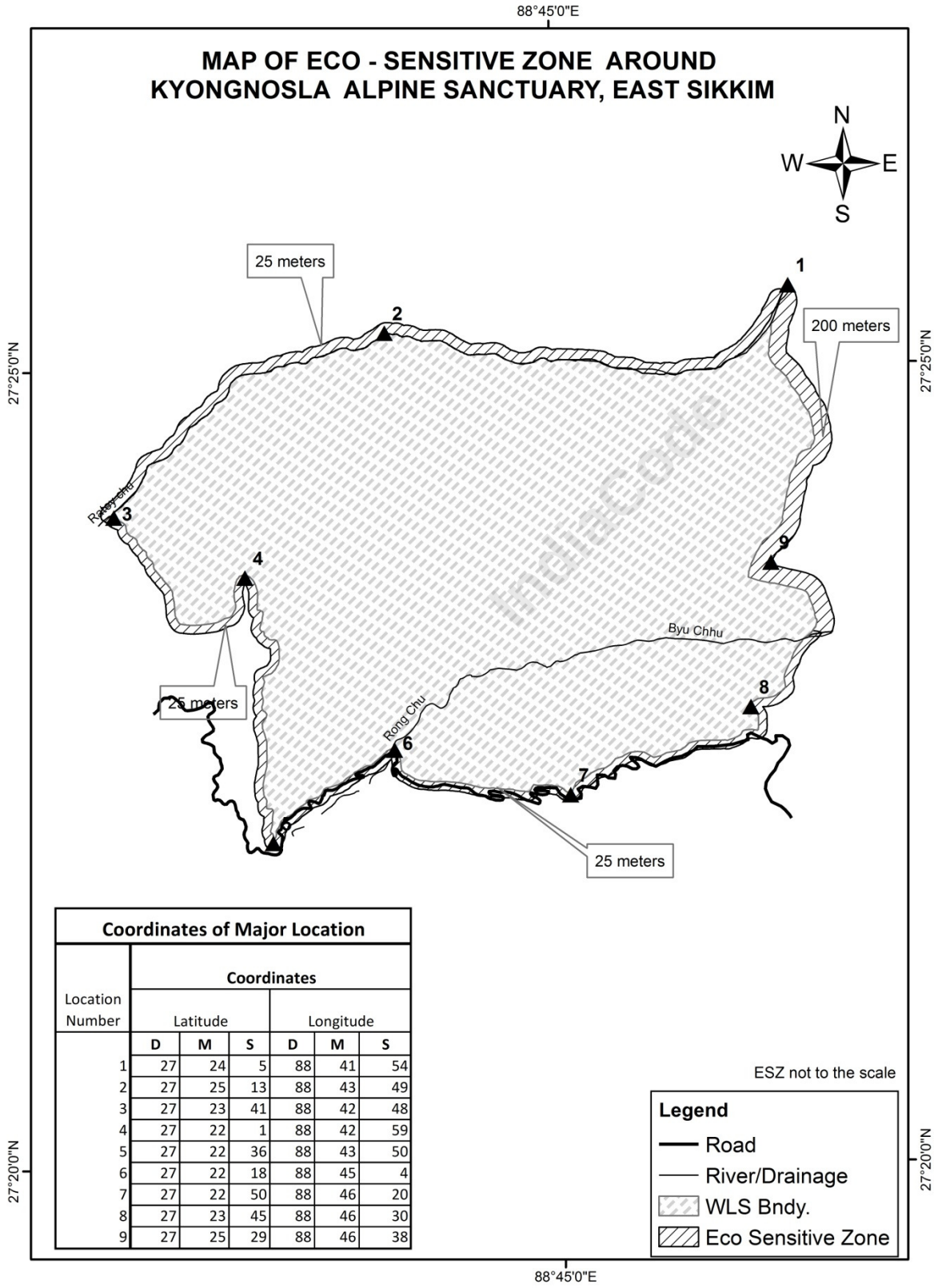
[F. No. 25/14/2013-ESZ-RE]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.



Coordinates of Major Location

Location Number	Coordinates					
	Latitude			Longitude		
	D	M	S	D	M	S
1	27	24	5	88	41	54
2	27	25	13	88	43	49
3	27	23	41	88	42	48
4	27	22	1	88	42	59
5	27	22	36	88	43	50
6	27	22	18	88	45	4
7	27	22	50	88	46	20
8	27	23	45	88	46	30
9	27	25	29	88	46	38

Annexure II

Village falling within the proposed Eco Sensitive Zone of Kyongnosla Alpine Sanctuary, East Sikkim.

Sl. No.	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Karponang	27	22	12	88	41	34
2.	Changu	27	22	14	88	44	40

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and data of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main not worthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan (Eco-sensitive Zone wise).
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise)
   Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment (EIA) Notifications, 2006 (Eco-sensitive Zone wise)
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under EIA Notification, 2006 (Eco-sensitive Zone wise)
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (Eco-sensitive Zone wise).
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.